# बिहार विधान परिषद्

## 188वां सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

## वर्ग – 5

शुक्रवार, तिथि — 18 फाल्गुन, 1939 (श.) / 09 मार्च, 2018 ई.

**प्रश्नों की कुल संख्या – 12**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शिक्षा विभाग | - | - | 10 |
| 2. | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | - | - | 02 |
| | | | कुल योग – | 12 |

## शिक्षकों को प्रशिक्षण

64. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग दो हजार से अधिक शिक्षक अप्रशिक्षित हैं, जिनके लिए शिक्षक नियोजन एवं सेवा-शर्त में संशोधन कर तीन वर्ष के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करने से संबंधित उपबंध जोड़ा गया था;

(ख) क्या यह सही है कि गत वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च, 2019 तक प्रशिक्षित करने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है और इस अवधि तक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से हटाने की बात कही गई है, जिससे राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों पर नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त तिथि में राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तमाम अप्रशिक्षित शिक्षकों को ओ.डी.एल. के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

## कम्प्यूटर की व्यवस्था

65. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ग दशम एवं बारहवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं की परीक्षा संबंधित सारी प्रक्रिया अब ऑन-लाइन कर दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि संबंधित विद्यालयों/महाविद्यालयों में कम्प्यूटर संबंधी सुविधा नहीं रहने से इस कार्य हेतु दूसरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण पंजीयन से लेकर परीक्षा प्रपत्रों में अनेकों त्रुटियां पाई जा रही हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु सभी सरकारी / संबद्धता प्राप्त संस्थानों में ही कम्प्यूटर कक्ष के साथ कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

## ताईक्वांडो प्रतियोगिता

66. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य स्कूल गेम्स ताईक्वांडो चैम्पीयनशिप प्रतियोगिता दिनांक 12.10.17 से 14.10.17 तक गोपालगंज में आयोजित की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि इसमें अंडर 17 वर्ष 55 कि.ग्रा. बालक वर्ग में मोतिहारी के सुधीर कुमार तथा बालिका वर्ग में अंडर 17 वर्ष के 42 कि.ग्रा. में अंजली कुमारी तथा 35 कि.ग्रा. में काजल कुमारी स्वर्ण पदक विजेता घोषित हुई;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में भाग लेने हेतु इन लोगों को कंकड़बाग के पाटलिपुत्रा स्टेडियम, पटना कैम्प के लिए बुलाकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता से वंचित कर ताईक्वांडो कोच अमर कुमार, अमरेन्द्र कुमार एवं राकेश कुमार द्वारा सिल्वर एवं ब्रोंज मेडल प्राप्त खिलाड़ियों का पैसों के प्रभाव से चयन कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिल्ली भेज दिया गया, क्या सरकार उक्त कोच एवं खेल विभाग के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

## स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड

67. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सूबे के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत हेतु स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना के तहत प्रति वर्ष पांच लाख विद्यार्थियों को शिक्षा लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है किन्तु वर्ष 2017 में मात्र 12 हजार विद्यार्थियों को ही लोन की सुविधा उपलब्ध हो सकी है;

(ग) क्या यह सही है कि सूबे के बैंकों के उदासीन रवैये की वजह से यह योजना अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु कौन-सा कारगर कदम उठाना चाहती है, और कबतक?

---

## सेवा-शर्त नियमावली

68. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विघटित विद्यालय सेवा बोर्ड से 2013 में अनुशंसित गणित और जीव विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति विशेष शिक्षक के रूप में विहित वेतनमान में की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि इन शिक्षकों के लिए कोई सेवा-शर्त नियमावली लागू नहीं है, जिसके कारण ये प्रोन्नति, स्थानान्तरण आदि से वंचित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन शिक्षकों पर भी 1983 की सेवा शर्त नियमावली लागू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

---

## वेतन आयोग की अनुशंसा

69. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को 01.4.2017 से सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का वित्तीय लाभ दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत तमाम शिक्षकों को अभी तक सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का वित्तीय लाभ नहीं दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अल्पसंख्यक विद्यालयों के तमाम शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का वित्तीय लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

---

## पहलवान का अखाड़ा

70. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में पहलवानों की कुश्ती के अभ्यास के लिए एक मात्र अखाड़ा बिछिया व्यायामशाला है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में हर साल सैकड़ों पहलवान कुश्ती की तैयारी करते हैं, लेकिन पहलवान की अपेक्षा के अनुरूप मैदान नहीं मिलता है, जिससे राज्य के पहलवान पलायन कर दूसरे राज्यों के अखाड़े से कुश्ती की तैयारी करते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तैयार करने के लिए राज्य के सभी जिलों में आधुनिक अखाड़ा बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

---

**स्थानांतरण का प्रावधान**

71. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन नियमावली 2006 में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात स्वीकृत पद के विरुद्ध उनके ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार यह बताएगी कि उक्त नियमावली में स्थानांतरण संबंधी किये गये प्रावधान को कबतक कार्यान्वित करना चाहती है?

---

**राशि निर्गत कबतक**

72. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में 5391 हाई एवं +2 स्कूल में से मात्र 2484 में ही पुस्तकालय की सुविधा है;

(ख) क्या यह सही है कि इन पुस्तकालयों में पुस्तकों की खरीद के लिए दी जाने वाली राशि भी नहीं मिल पा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे पुस्तकालय की सुविधा एवं किताबों के लिए राशि निर्गत कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

---

## कमरे का निर्माण

73. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारूण प्रखंड के ग्राम खण्डा शेखबिगहा के उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय में मात्र दो कमरे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि कमरों की संख्या कम होने के कारण बच्चों को बैठने की जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण पढ़ाई-लिखाई बाधित हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में कमरों का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

## उचित कार्रवाई

74. **श्री सी.पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मगध विश्वविद्यालय में छात्र सूचना केन्द्र के कैंटिन निर्माण पर एक करोड़ 8 लाख 54 हजार 500 रुपये खर्च किए गए, लेकिन इसके लिए कोई टेंडर नहीं निकाला गया;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विश्वविद्यालय ने चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के आवास निर्माण पर 4 करोड़ 81 लाख 35 हजार रुपये खर्च किया, जिसपर वित्त परामर्शी ने आपत्ति व्यक्त की थी, लेकिन ठेकेदार को राशि का भुगतान कर दिया गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य में नियमानुकूल कार्य नहीं करने के लिए जांचोपरांत उचित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

## दंडात्मक कार्रवाई

75. **श्री राम लषण राम रमण** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि तिथि 19.01.2018 को दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में प्रकाशित खबर के अनुसार समस्तीपुर के तत्कालीन डी.पी.ओ. (योजना एवं लेखा) श्री राजेन्द्र मिश्र ने 60,03,500 (साठ लाख तीन हजार पांच सौ रुपये) रुपये (साइकिल पोशाक योजना) का घोटाला किया था;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने समस्तीपुर के तत्कालीन डी.पी.ओ. सह वर्तमान में मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेन्द्र मिश्र पर वित्तीय अनियमितता के लिए प्राथमिकी दर्ज करने, निलम्बित करने तथा घोटाले की राशि की वसूली का आदेश शिक्षा विभाग को दिया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उपरोक्त मामले में दंडात्मक कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

---

**सुनील कुमार पंवार**
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 09 मार्च, 2018